

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :-

जगदीश प्रसाद गौड़  
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 75/2021

1. इन्द्रसिंह पुत्र मातुराम जाति जाट, निवासी भैंसावता, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।
2. रणबीर पुत्र मातुराम जाति जाट, निवासी भैंसावता, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

-अपीलार्थी

-बनाम-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।
2. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, सिंघाना, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।
3. कमला पत्नी अशोक कुमार जाति जाट निवासी माकड़ो तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।

- रेस्पोंडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना  
उनवानी सरकार बनाम बनवारी अंधारा 91 (क) एल0आर0एक्ट 1956  
मु0न0 01/2021 निर्णय दिनांक 05.08.2021

उपस्थिति:-

1. श्री राजेश पूनियां, एडवोकेट ----- अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट ----- रेस्पोंडेन्ट नंबर-2 की ओर से।
3. श्री मनोज कुमार वर्मा, एडवोकेट ----- रेस्पोंडेन्ट नंबर-3 की ओर से।

-निर्णय-

दिनांक 21 जनवरी, 2022

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 05.08.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम इन्द्र वगैरह मु0नं0 01/2021 अ. धारा 91(क) एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार बुहाना के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि- हल्का पटवारी माकड़ो द्वारा नायब तहसीलदार सिंघाना के समक्ष पेश रिपोर्ट में राजस्व ग्राम हुक्मा की ढाणी में भूमि हाल खसरा नम्बर 729/684 रकबा 0.94 हैक्टर किस्म बजड़ बिना आवासीय रूपान्तरण के 2000 वर्ग मीटर भूमि पर इन्द्र सिंह व रणबीर पुत्रान मातुराम, जाति जाट निवासी भैंसावता खुर्द हाल निवासी चिड़ावा रोड़ ढाणी हुक्मा में चारदिवारी एवं आवासीय निर्माण नियम विरुद्ध किया है। पटवारी की



अति. जिला कलक्टर  
झुन्झुनू

उक्त शिकायत पर अपीलान्त के विरुद्ध धारा 90: क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना के यहां अपीलान्त के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। राजस्व अधिकारियों की बैठक दिनांक 02.07.2021 में श्रीमान जिला कलक्टर ने निर्देश दिया कि धारा 90:क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार भूमिधारी तहसीलदार को होता है। जिसके फलस्वरूप उपरोक्त प्रकरण न्यायालय तहसीलदार बुहाना को भेज दिया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना ने अपीलान्त को साक्ष्य सबूत व दस्तावेज पेश करने का अवसर दिये बिना ही आलौच्य निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्त द्वारा उपरोक्त निर्माण फसल सुरक्षा एवं भूमि सुधार हेतु करवाया है। विवादित भूमि के संबंध में अदालत मातहत में अपीलान्त ने अपने जबाब में लिखा है कि अपीलान्त का खसरा नम्बर 729/684 से कोई ताल्लुक नहीं है। अपीलान्त ने उक्त भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया है। अपीलान्त जिस भूमि पर काबिज है उस भूखण्ड की एकाकी मालिक सुनिता पत्नि रणबीर सिंह है। अपीलान्त द्वारा उक्त तथ्य का अदालत मातहत के समक्ष खुलासे के बाद अदालत मातहत को भूखण्ड मालिक को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया। मौजूदा प्रकरण में शिकायतकर्ता स्वयं पटवारी हल्का माकड़ो है जो लोकसेवक है। पटवारी हल्का ने अपनी शिकायत व मौका रिपोर्ट में यह नहीं लिखा कि अपीलान्त के कब्जे के अलावा उक्त जमीन खाली है या आबादी बसी है। उक्त जमीन खसरा नंबर 729/684 पूर्णतया आबाद काफी लोगों ने रिहायशी मकान बना रखे हैं। मौके पर उक्त जमीन कृषि भूमि का पूर्णतया उपयोग आबादी के लिए हो रहा है वहां भूमिधारी आबादा व्यक्तियों को बेदखल नहीं कर सकता बल्कि रूपान्तरण नियमों के तहत रूपान्तर दर की राशि जमा करवा सकता है। अपीलान्त के विरुद्ध धारा 90 क: राज.ले.रेवन्यु एक्ट की कार्यवाही अदालत मातहत ने एक पक्षीय व नियम विरुद्ध की है। धारा 90:क: एलआरएक्ट की कार्यवाही जमीन के रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध ही हो सकती है। अदालत मातहत ने उक्त जमीन के रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध धारा 90:क: एल.आर.एक्ट की कार्यवाही क्यों नहीं की, क्या कारण रहा, ऐसा अंकन आलौच्य निर्णय में नहीं है। अपीलान्त एक सद्भाविक क्रेता है। अपीलान्त के विरुद्ध धारा 90 क: एल.आर.एक्ट के प्रावधान अपलीकेबल नहीं होते। अदालत मातहत ने निर्णय पारित करने में अपीलान्त की जवाबदेही का नजरअंदाज किया है। अपीलान्त का क्यशुदा भूखण्ड गत खसरा नंबर 351/3 का भाग है खसरा नंबर 351/3 की

ज.स.स.  
जिला कलक्टर  
भुवनेश्वर

जमीन रेल्वे विभाग की जमीन से सटकर है जिसमें से रेल्वे विभाग ने 3 बीघा 8 विश्वा जमीन अधिग्रहण की है। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय पारित करने में अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की है। उप तहसील सिंघाना के यहां दिनांक 19.7.2021 को पत्रावली भूमिधारी तहसीलदार बुहाना पत्रावली भेजने बाबत अपीलान्ट व उसके अधिवक्ता को सूचना नहीं दी। कानून से तहसीलदार बुहाना को अपने न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने बाबत सूचना देनी चाहिये थी, बरोज निर्णय दिनांक 5.8.2021 को भी आदेशिका में लिखा है कि अतिक्रमी खातेदार अनुपस्थित। इस प्रकार अदालत मातहत ने प्रक्रियात्मक विधि के प्रावधानों की अनदेखी की है तथा आलौच्य निर्णय पारित करने में अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की है। योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ पत्रावली व कानून होने से खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना का निर्णय दिनांक 05.08.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- हल्का पटवारी माकड़ो द्वारा नायब तहसीलदार सिंघाना के समक्ष पेश रिपोर्ट में राजस्व ग्राम हुक्मा की ढाणी में भूमि हाल खसरा नम्बर 729/684 रकबा 0.94 हैक्टर किस्म बजड़ बिना आवासीय रूपान्तरण के 2000 वर्ग मीटर भूमि पर इन्द्र सिंह व रणबीर पुत्रान मातुराम, जाति जाट निवासी भैंसावता हाल निवासी चिड़ावा रोड़ ढाणी हुक्मा में चारदिवारी एवं एक आवासीय कमरा निर्माण नियम विरुद्ध किया है। पटवारी की उक्त शिकायत पर अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 90: क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना के यहां अपीलान्ट के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। राजस्व अधिकारियों की बैठक दिनांक 02.07.2021 में श्रीमान जिला कलक्टर ने निर्देश दिया कि धारा 90:क राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज प्रकरण की सुनवाई का क्षेत्राधिकार भूमिधारी तहसीलदार को होता है। जिसके फलस्वरूप उपरोक्त प्रकरण न्यायालय तहसीलदार बुहाना को भेज दिया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना ने अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत व दस्तावेज पेश करने का अवसर दिये बिना ही आलौच्य

अति. जिला कलक्टर  
झुंझुनू

निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्त द्वारा उपरोक्त निर्माण फसल सुरक्षा एवं भूमि सुधार हेतु करवाया है। विवादित भूमि के संबंध में अदालत मातहत में अपीलान्त ने अपने जबाब में लिखा है कि अपीलान्त का खसरा नम्बर 729/684 से कोई ताल्लुक नहीं है। अपीलान्त ने उक्त भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया है। अपीलान्त जिस भूमि पर काबिज है उस भूखण्ड की एकाकी मालिक सुनिता पत्नि रणबीर सिंह है। अपीलान्त द्वारा उक्त तथ्य का अदालत मातहत के समक्ष खुलासे के बाद अदालत मातहत को भूखण्ड मालिक को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया। मौजूदा प्रकरण में शिकायतकर्ता स्वयं पटवारी हल्का माकड़ो है जो लोकसेवक है। पटवारी हल्का ने अपनी शिकायत व मौका रिपोर्ट में यह नहीं लिखा कि अपीलान्त के कब्जे के अलावा उक्त जमीन खाली है या आबादी बसी है। उक्त जमीन खसरा नंबर 729/684 पूर्णतया आबाद काफी लोगों ने रिहायशी मकान बना रखे हैं। मौके पर उक्त जमीन कृषि भूमि का पूर्णतया उपयोग आबादी के लिए हो रहा है वहां भूमिधारी आबादा व्यक्तियों को बेदखल नहीं कर सकता बल्कि रूपान्तरण नियमों के तहत रूपान्तर दर की राशि जमा करवा सकता है। अपीलान्त के विरुद्ध धारा 90 क: राज.ले.रेवन्यु एक्ट की कार्यवाही अदालत मातहत ने एक पक्षीय व नियम विरुद्ध की है। धारा 90:क: एलआरएक्ट की कार्यवाही जमीन के रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध ही हो सकती है। अदालत मातहत ने उक्त जमीन के रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध धारा 90:क: एल.आर.एक्ट की कार्यवाही क्यों नहीं की, क्या कारण रहा, ऐसा अंकन आलौच्य निर्णय में नहीं है। अपीलान्त एक सद्भाविक क्रेता है। अपीलान्त के विरुद्ध धारा 90 क: एल.आर.एक्ट के प्रावधान अपलीकेबल नहीं होते। अदालत मातहत ने निर्णय पारित करने में अपीलान्त की जवाबदेही का नजरअंदाज किया है। अपीलान्त का क्यशुदा भूखण्ड गत खसरा नंबर 351/3 का भाग है खसरा नंबर 351/3 की जमीन रेल्वे विभाग की जमीन से सटकर है जिसमें से रेल्वे विभाग ने 3 बीघा 8 विश्वा जमीन अधिग्रहण की है। अदालत मातहत ने आलौच्य निर्णय पारित करने में अपीलान्त के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की है। उप तहसील सिंघाना के यहां दिनांक 19.7.2021 को पत्रावली भूमिधारी तहसीलदार बुहाना पत्रावली भेजने बाबत अपीलान्त व उसके अधिवक्ता को सूचना नहीं दी। कानून से तहसीलदार बुहाना को अपने न्यायालय में प्रकरण दर्ज होने बाबत सूचना देनी चाहिये थी, बरोज निर्णय दिनांक 5.8.2021 को भी आदेशिका में लिखा है कि अतिक्रमी खातेदार अनुपस्थित। इस प्रकार अदालत मातहत ने प्रक्रियात्मक विधि के

11/11/21  
अति. जिला कलक्टर  
बुधनूर

प्रावधानों की अनदेखी की है तथा आलौच्य निर्णय पारित करने में अपीलांट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना नहीं की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना का निर्णय दिनांक 05.08.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस रैस्पोंडेंट नंबर 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा अपीलांट को विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस तरह की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई कि विवादित भूमि पर उनके द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बाद ही निर्माण कार्य किया हो। विवादित भूमि ना तो अपीलांट की क्रयसुदा भूमि है और ना ही किसी अन्य प्रकार से अपीलांट के अधिकार क्षेत्र की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.08.2021 विधिसम्मत है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन तथ्यों पर आधारित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

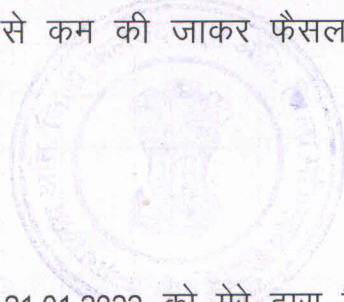
दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रैस्पोंडेंट नंबर -3 का कथन है कि विवादित भूमि उसकी क्रयसुदा खातेदारी भूमि है। अपीलांट इन्द्र वगैरह द्वारा विवादित भूमि को छोड़कर अन्य भूमि के क्रय के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। विवादित भूमि से इसका कोई लेना देना नहीं है। अपीलांट ने अवैध रूप से निर्माण कर रखा है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.08.2021 की पालना करवाने का निवेदन किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पटवारी हल्का माकड़ों की रिपोर्ट दिनांक 14.06.2021 के अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम हुकमा की ढाणी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 729/684 कुल रकबा 0.94 हैक्टर पर बनवारी पुत्र श्योदान द्वारा अवैध रूप से 1000 वर्ग मीटर भूमि पर बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के एवं भूमि के रूपान्तरण के बिना निर्माण कार्य किये जाने पर अपीलांट को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सुना गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार

31/11/21  
अति. जिला क्लर्क  
झुंझुनू

बुहाना एवं हाजा न्यायालय के समक्ष इस तरह की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई कि जिससे विवादित भूमि पर उसका निर्माण वैध साबित होता हो। अपीलांत द्वारा विवादित भूमि पर बिना भू रूपान्तरण करवाये अवैध निर्माण कार्य किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांत को नोटिस खसरा नंबर 729/684 रकबा 0.94 में बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के निर्माण करना बताया जाकर दिया गया है, जिसके संबंध में अपीलांत द्वारा कोई ठोस साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रकरण में अपीलांत द्वारा कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से गैर कृषि प्रयोजन हेतु निर्माण करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना के निर्णय दिनांक 05.8.2021 द्वारा विवादित भूमि से अपीलांत को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती। क्योंकि अपीलांत ना तो कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है और ना ही उसके द्वारा किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्माण कार्य किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.08.2021 उनवानी सरकार बनाम इन्द्र वगैरह मु0नं0 01/2021 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।



(जे0 पी0 गौड़)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 21.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,  
झुंझुनू